VISION IAS

15 JUL 22

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1815)

Name of Candidate	जतिन पाराशर		
Medium Eng./Hindi	हिन्दी	Registration Number	674865
Center	मुखर्जी नगर	Date	15/07/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. Identify the major features of Digital India Land Record Modernization Programme. Can you foresee any challenges in its implementation? Also, suggest measures to ensure its smooth roll out.

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। क्या आप इसके कार्यान्वयन में किन्हीं चुनौतियों का पूर्वानुमान कर सकते हैं? साथ ही, इसके सुचारू शुरुआत को सुनिश्चित करने के उपायों का भी सुझाव दीजिए।

भारत में भू- अभिलेखों में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए 2015 से डिजीटल इंडिया भू- अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य

- भारत के समस्त भू अभिलेखों का डिजीटलीकरण
- संबंधित डिजीटल रिकार्ड को सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करना।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

(1) अखिल भारतीय स्तर पर संचालन: कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय स्तर पर किया जायेगा तथा अंतिम गांवों की भूमि रिकार्ड को भी डिजीटल किया जायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय : कार्यक्रम संचालन में अंतरिक्ष विभाग (ISRO का भुवन App), ग्रामीण पंचायत विभाग तथा कृषि मंत्रालय शामिल हैं व समन्वय से कार्य कर रहे हैं।

iii) प्रौद्योगिकी का प्रयोग : ड्रोन, उपग्रह चित्र आदि माध्यमों का प्रयोग कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पहुँच आसान बनायेगा।

iv) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना : योजना का संचालन राज्यों की सहायता से किन्तु सम्पूर्ण वित्तीय आवंटन केन्द्र द्वारा।

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

---

i) वर्तमान अभिलिखित से असमानता होने पर विवाद का समाधान कैसे किया जायेगा।

ii) इतने विशाल डेटा का संग्रह, सुरक्षा तथा उसे लगातार update करना।

iii) भारत में भूमि पर महिलाओं का स्वामित्व हेतु योजना में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

iv) वनवासी क्षेत्रों में परम्परागत भूमि अधिकार, रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं उनका सर्वेक्षण किस प्रकार।

इस कार्यक्रम की सफलता केन्द्र-राज्य समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति (कर्नाटक में 90% कार्य पूरा), अधिक प्रशिक्षित मानव संसाधन नियोजन तथा उपयुक्त विवाद समाधान तंत्र की स्थापना में निहित है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss the effects of using 'monetization of fiscal deficit' as a policy on the economy of a country.

किसी देश की अर्थव्यवस्था पर नीतिगत रूप में 'राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण' का उपयोग करने के प्रभावों की विवेचना कीजिए।

सरकार के कुल सार्वजनिक व्यय की सार्वजनिक राजस्व से अधिकता [राजकोषीय घाटे] को विभिन्न स्रोतों से ऋण लेकर पूरा किया जाता है। यद्यपि भविष्य में चुकाये जाने वाले इन ऋणों से बचने हेतु घाटे का मुद्रीकरण एक विकल्प है।

घाटे का मुद्रीकरण

- RBI के माध्यम से प्रत्यक्ष मुद्रा निर्गमन द्वारा घाटे की पूर्ति
- RBI को सरकारी बाण्डों का विक्रय कर ऋण प्राप्त करना

घाटे का तत्कालीन * COVID-19 की परिस्थितियों ने घाटे के मुद्रीकरण को एक मुद्दे के रूप में सामने प्रस्तुत किया है। जिसमें अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों लाभ होते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

घाटे के मुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था को लाभ

i) राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण : चूँकि इस प्रकार से घाटे की पूर्ति को बजट में शामिल नहीं किया जाता अत: राजकोषीय घाटा स्थिर बना रहता है।

ii) क्रेडिट रेटिंग स्थिरता : राजकोषीय घाटे में वृद्धि के साथ ~~देश~~ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की ~~क्रेडिट~~ क्रेडिट रेटिंग गिरने की सम्भावना होती है किन्तु घाटे की स्थिरता से रेटिंग भी स्थिर रहती है।

iii) अर्थव्यवस्था में माँग सृजित करना : सरकारी व्यय में वृद्धि से लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि होती है परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में माँग सृजित होती है।

iv) आधारभूत संरचनात्मक सुधार : सरकार इस प्रकार धन का उपयोग अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों (परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य) पर व्यय कर सकती है जिससे आर्थिक वृद्धि बनी रहती है।

v) COVID-19 परिस्थितियों में मुद्रा संचलन धीमा होने के कारण इसका ~~प्रभाव~~ अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव

i) मुद्रास्फीति दबाव : अत्यधिक माँग के सृजन के अनुपात में उत्पादन में वृद्धि न होने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है।

ii) मुद्रा का अवमूल्यन : विदेशी मुद्रा के समक्ष घरेलू मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि,, क्रयशक्ति क्षमता को कमजोर बनाती है। घरेलू मुद्रा की

iii) राजकोषीय अनुशासन के भटकाव :- इसके प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं कि जब भी खर्चा करने चार की अधिकता रही सरकार द्वारा गैर-पूँजीगत गतिविधियों में उसका व्यय किया गया है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

स्पष्टतः राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण के अर्थव्यवस्था पर मिले-जुले प्रभाव होते हैं तथापि सरकारों को आवश्यकता अनुसार निर्णय करना चाहिए व घाटे की पूर्ति के अन्य उपायों (राजस्व व्यय में कमी, कर व गैर आय में बढ़ोत्तरी) पर भी विचार करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Explaining the need for direct tax reforms, mention the steps taken recently to improve the direct tax ecosystem in India.

प्रत्यक्ष कर सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए, भारत में प्रत्यक्ष कर परिवेश में सुधार लाने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

प्रत्यक्ष कर (जिनका कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर होता है) राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तथा सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों की माँग काफी समय से की जा रही है।

भारत में प्रत्यक्ष कर सुधारों की आवश्यकता

i) निम्न प्रत्यक्ष कर आधार : भारत में केवल 1.67% जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष करों का भुगतान जिसे बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

ii) प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष कर अनुपात : भारत में OECD के 67:33 अनुपात के विपरीत 65:35 के साथ अप्रत्यक्ष करों की प्रधानता है। जिसे बदलने की आवश्यकता है।

iii) प्रत्यक्ष करों में अत्यधिक छूटें व कटौतियाँ : जिन्हें समायोजित कर कर का अपवंचन शैली व कर परिहार शैली प्रथाओं को कम किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) कर अधिनियमों में त्रुटियाँ, अस्पष्ट व Cross Reference

भारतीय कर अधिनियम अत्यधिक त्रुटियों, अस्पष्ट परिभाषाओं तथा Cross Reference से भरे हुए जिससे कर प्रावधानों में जटिलता आती है तथा यह गलत प्रयोग को बढ़ावा देते हैं।

v) कर विवादों की अत्यधिक संख्या

न्यायपालिका कर विवादों के बोझ से भरी पड़ी है जो मान्यता, कर अधिनियमों में व्याप्त अस्पष्टता के कारण है अतः विवादों को कम करने हेतु कर सुधार आवश्यक है।

प्रत्यक्ष कर सुधारों का स्पष्ट लाभ

सरकार को के राजस्व में वृद्धि के रूप में होगा जो अभी राजकोषीय घाटे के नियंत्रण को लेकर चिंतित रहती है। व्यय हेतु उपलब्ध राशि का उपयोग अर्थव्यवस्था को वृद्धि देने में किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष कर परिवेश में सुधार लाने उठाए गए कदम

i) प्रत्यक्ष कर संहिता : स्पष्ट परिभाषा, सरल प्रावधान तथा न्यूनतम Cross Refrence के साथ कर अधिनियमों की संहिता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को मान्यता

Base Erosion and Profit shifting जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रथाओं को समाप्त करने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 15% का न्यूनतम वैकल्पिक कर।

भारत को इससे कुल राजस्व प्राप्ति के 6% तक लाभ का अनुमान

iii) कर विवाद समाधान योजना: वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष कर विवादों का तीव्रता से समाधान करने हेतु।

iv) Big Data Analysis: विमुद्रीकरण के पश्चात विभिन्न खातों की जाँच के बाद कर संबंधी नोटिस जिसका लाभ आयकर रिटर्नों की संख्या में तेजी के रूप में देखा गया।

v) E-commerce, तथा Google जैसी कम्पनियों पर 6% की Equalization Levy का आरोपण किया गया।

अतः भारत में प्रत्यक्ष कर आधार में बढ़ोत्तरी आवश्यक है ताकि आय पुनर्वितरण उपायों का संचालन तथा सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रभावी रूप से उपलब्ध कराकर SDG लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Identifying the essential characteristics of money, discuss whether cryptocurrencies can emerge as a credible form of money.
मुद्रा की अनिवार्य विशेषताओं की पहचान करते हुए, चर्चा कीजिए कि क्या क्रिप्टोकरेंसीज मुद्रा के एक विश्वसनीय प्रकार के रूप में उभर सकती हैं।

मुद्रा सरकार द्वारा प्रमाणित, वस्तुओं / सेवाओं के भुगतान का एक माध्यम है। प्रत्येक देश की स्वयं की एक मुद्रा होती है। मुद्रा विभिन्न प्रकार की हो सकती है जिसमें वर्तमान में डिजीटली प्रचलित मुद्रा क्रिप्टोकरेंसी को भी शामिल किया जा सकता है।

मुद्रा की अनिवार्य विशेषताएँ

i) निश्चित मान: मुद्रा का एक निश्चित मूल्य होता है जिसके बदले में उसी मान की वस्तु/सेवा का क्रय किया जा सकता है।

ii) स्वीकृति: मुद्रा में स्वीकृति का गुण होता है तथा व्यक्ति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है।

iii) निश्चित धात्विक भार: अर्थात् मुद्रा के पीछे एक निश्चित भार होता है जो उसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति करता है।

iv) समान मान: मुद्रा का मान सदैव समान रहता है उसका क्षरण नहीं होता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~क्रिप्टोकरंसी~~

क्रिप्टो करंसी

i) Blockchain टैक्नोलॉजी पर आधारित आभासी मुद्रा जिसे किसी भी राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है।

जैसे:- Bit coin, एथेरियम आदि।

क्रिप्टो करेंसी की विश्वसनीय रूप में उभरने की संभावना

संभावना है!-

i) इसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तेजी से मान्यता प्राप्त हो रही है
ऐसा पहला राष्ट्र जिसने इसे लीगल टेण्डर घोषित किया।

ii) चीन, जापान, आदि देशों द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है।

iii) नियंत्रण के अधीन होने से इसके माध्यम से ~~हस्तांतरण~~ अन्तर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सरल व आसान है।

iv) तेजी से निवेश का माध्यम बनती जा रही है व विभिन्न E-commarce प्लेटफार्म पर भी स्वीकार्य है।

संभावना नहीं है :-

i) अत्यधिक अस्थिरता, COVID-19 के समय लगातार तेजी से बढ़त व कमजोरी देखी गई।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

ii) इसके पीछे किसी राष्ट्र का या अन्य संलग्नता न होने के कारण मूल्य निर्धारण कठिन है।

iii) धनशोधन, आतंकवादी वित्तपोषण आदि में तेजी से बढ़ते उपयोग के कारण कई राष्ट्रों द्वारा इस पर अवैध प्रतिबंध आरोपित किये गये हैं।
जैसे-भारत।

iv) भारत में RBI द्वारा स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि क्रिप्टो में निवेश से निवेशकों को बड़ी हानि हो सकती है।

v) विश्व में डिजीटल डिवाइड:- यद्यपि विश्व भी में विभिन्न राष्ट्रों में इसका तेजी से उपयोग किन्तु एक बड़ी आबादी की पहुँच से अभी भी दूर है।

यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात् भारत में क्रिप्टो मुद्रा वैध है किन्तु सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई। सरकार को सभी हितधारकों से विमर्श तथा गहन समीक्षा के बाद ही क्रिप्टो को लेकर किसी ~~नतीजे~~ नतीजे पर पहुंचना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Balance of payment crisis results from multiple factors. Enlist these factors and explain the ways in which an economy can sustainably address such crisis.

भुगतान संतुलन का संकट अनेक कारकों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। इन कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और उन तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनसे एक अर्थव्यवस्था ऐसे संकट का संधारणीय रूप से समाधान कर सकती है।

निश्चित समय (वित्तीय वर्ष) राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र से किये गये वस्तु, सेवाओं व परिसंपत्तियों के लेन-देन का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। इसके अंतर्गत 2 खातों

i) व्यापार चालू खाता (वस्तु-सेवा लेन-देन)
ii) पूंजी खाता (परिसंपत्ति लेन-देन)

को शामिल किया जाता है।

भुगतान संतुलन का संकट

जब किसी देश द्वारा लगातार निर्यात से अधिक आयात किया जाता है तो उस राष्ट्र के पास आगे और आवश्यक सामग्री के आयात हेतु अपर्याप्त विदेशी मुद्रा शेष रहती है जिसके कारण उसकी आयात असमर्थता को भुगतान संतुलन का संकट कहा जाता है।

भुगतान संतुलन संकट के कारण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

i) अत्यधिक आयात निर्भरता: इसके कारण तेजी से विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी आती है तथा उत्पादों की कीमत बढ़ने पर अस्थिरता आती है।

ii) कठोर मुद्रा विनियमन: जिसके कारण विदेशी मुद्रा का आगमन बाधित होता है।

iii) न्यून निर्यात: विदेशी मुद्रा का आगमन नहीं हो पाता है तथा मुद्रा भण्डार में कमी आती है।

iv) अर्थव्यवस्था की प्रकृति: बंद अर्थव्यवस्था में बाहरी निवेश FDI व FPI की अनुमति नहीं होती है जिसका परिणाम विदेशी मुद्रा भण्डार की मात्रा पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

v) वैश्विक स्थितियाँ: वैश्विक स्थितियाँ भुगतान असंतुलन को भुगतान संकट में परिवर्तित कर सकती हैं।

उदा-) 1991 में USSR के विघटन से भारतीय निर्यात में कमी तथा खाड़ी देशों के युद्ध के कारण तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि का प्रभाव।

-) वर्तमान में COVID-19 के कारण श्रीलंका के पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव का परिणाम।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

vi) राजनैतिक स्थिरता : स्थिर राजनैतिक सरकारें देश की संवृद्धि को बनाए रखने हेतु तेजी से निर्णय लेती हैं, देश की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होने से विदेशी पूंजी का तेजी से आगमन होता है।

संधारणीय रूप से समाधान के उपाय

i) आयात प्रतिस्थापन नीतियों के स्थान पर अधिक निर्यात द्वारा आयात की पूर्ति पूर्ति करना।

ii) विदेशी पूंजी निवेश को सुविधा के अनुसार प्रोत्साहित करना।

iii) देश का समग्र आर्थिक विकास, राजकोषीय अनुशासन आदि संपूर्ण क्रेडिट रेटिंग को उच्च बनाए रखता है जिससे सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है।

iv) आयात निर्भरता का विविधिकरण करना : जिस प्रकार भारत अपनी ऊर्जा आयात निर्भरता को सौर ऊर्जा, आदि द्वारा कम कर रहा है।

v) विदेशी ऋण को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में आधारभूत सुविधाओं पर व्यय करना ताकि आर्थिक ढांचा मजबूत हो सके।

vi) एक विकासशील राष्ट्र हेतु निश्चित सीमा के अधीन भुगतान असंतुलन प्रायः अच्छा माना जाता है किन्तु इस पर ध्यान रखे जाने हेतु सशक्त केन्द्रीय बैंक भी उपस्थित होना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. What are the reasons for low tax-to-GDP ratio in India? Highlight the steps taken by the government to tackle this issue.
भारत में निम्न कर-जी.डी.पी. अनुपात (टैक्स-टू-जी.डी.पी. रेश्यो) के क्या कारण हैं? इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए।

भारत कर-GDP अनुपात

OECD राष्ट्रों के 34% के मुकाबले 10% के आसपास निम्न स्तर पर है।

भारत में निम्न कर-GDP अनुपात के कारण

i) छोटा कर आधार: भारत में केवल 1.6% जनसंख्या द्वारा कर भरा जाता है। भारत में व्याप्त गरीबी का दोष्य को कम बनाये रखे हुए है।

ii) अप्रत्यक्ष करों की प्रधानता: OECD राष्ट्रों के 33% के मुकाबले भारत में 65% कर राजस्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है।

iii) अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रधानता:
भारत में 92% श्रम असंगठित है जो कर अनुपालन के अधीन नहीं है।

iv) कमजोर कर प्रशासन: कर अनुपालन में कमियाँ, राजस्व संग्रह की उच्च लागत तथा जटिल कर प्रावधान का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रशासन को कमजोर बनाते हैं।

4) कर अपवंचन व कर परिहार : भारत में कृषि आय पर कर आरोपित नहीं किया जाता तथा बड़ी कम्पनियाँ लाभ हस्तांतरण आदि माध्यमों का लाभ लेकर कर बचत करती हैं।

इनसे निपटने सरकार द्वारा उठाये गये कदम

---

① प्रत्यक्ष कर संहिताकरण : सरल, स्पष्ट व सुपरिभाषित कर प्रावधानों के साथ कर संहिता का निर्माण।

② कर विवादों में कमी लाने वित्त मंत्रालय द्वारा विश्वास योजना का प्रारंभ।

③ अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है ताकि नियमों का उचित अनुपालन।

④ भारत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कर अपवंचन की प्रथाओं को समाप्त करने OECD देशों के साथ BEPS Project पर कार्य कर रहा है।

⑤ E-Commerce आदि डिजीटल कम्पनियों पर 6% की Equilization levy लगाई गई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) GST को पारित किया गया जो एक देश एक कर प्रणाली लागू करता है तथा छोटे-छोटे उद्योगों को भी कर व्यवस्था में शामिल होने में सहायक है।

(7) भारत में कर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

यद्यपि सरकार के प्रयास सही दिशा में हैं किन्तु निश्चित सीमा से ऊपर कृषि आय पर कर, सरल अनुपालन उपाय, विवाद से निपटान संबंधी प्रयासों को भी लागू किये जाने की आवश्यकता है।

———— x ———— x ————

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Explaining the meaning of privatisation of public sector enterprises, provide its merits and demerits in the context of India.
सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के निजीकरण का अर्थ समझाते हुए, भारत के संदर्भ में इसके गुणों और दोषों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।

सरकार द्वारा अपने उद्यमों (केन्द्रीय / राज्य उद्यमों) में हिस्सेदारी को घटाकर 51% से नीचे ले आना तथा प्रबंधन को निजी हाथों में सौंप देना सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों का निजीकरण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है:-

(1) अपूर्ण निजीकरण :- उद्यम में कुछ हिस्सेदारी बनाए रखना।

(2) पूर्ण निजीकरण : 100% हिस्सेदारी निजी क्षेत्रक को सौंप देना।
जैसे) एयर इण्डिया को टाटा को सौंप दिया गया।

भारत में 1991 के सुधारों के पश्चात् ही निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी जो HMT, मारुति से होते हुए वर्तमान में एयर इण्डिया तक पहुँची है।

निजीकरण के गुण

(1) सरकार पर अप्रत्याशित वित्तीय बोझ में कमी आती है तथा सार्व उद्यमों का प्रयोग निजी क्षेत्रक द्वारा प्रतिस्पर्धा, दक्षता तथा लाभ के माध्यम से किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) सरकार को गैर-जरूरी मांगों का अराजनीतिकरण करने में सहायता मिलती है।

(3) निजीकरण से सरकार को आय प्राप्त होती है जिसका उपयोग सरकार आधारभूत संरचना में निवेश तथा सामाजिक उद्देश्यों (शिक्षा, स्वास्थ्य) की पूर्ति कर सकती है जिससे आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

(4) निजीकरण के से निजी क्षेत्र के पूंजी प्रवाह में वृद्धि होती है व आर्थिक प्रगति को तेजी मिलती है।

(5) कार्पोरेट कार्य संस्कृति, रणनीतिक प्रबंधन आदि माध्यमों से अलाभकारी ~~उद्य~~ उद्यम को लाभकारी उद्यम में परिवर्तित कर अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाती है।

(6) निर्यात उन्मुखता तथा नागरिकों को सस्ती कीमत पर अधिक ~~अन्य~~ विकल्प उपलब्धता होती है।

निजीकरण के दोष

(1) सम्पूर्ण निजीकरण आर्थिक-सामाजिक शक्ति को कुछ ~~ही~~ हाथों में केन्द्रित कर सकता है जिससे बाजार में एकाधिकार व अल्पाधिकार जैसी प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय संतुलन तथा सामाजिक सुभेद्य वर्गों का ध्यान नहीं रख सकता है।

(3) सरकारी उद्यमों का, विदेशी हाथों में निवेश राष्ट्र की शक्ति व संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न कर सकता है।

(4)

निजीकरण
भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण समय की मांग है किन्तु सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि विशाल सुभेद्य वर्ग पर निजीकरण के हानिकारक प्रभावों का ओझल नहीं किया जा सकता है भारत को इस क्षेत्र में आंशिक व रणनीतिक विनिवेश द्वारा धीरे-धीरे कदम बढ़ाना चाहिए तथा विनिवेश को साध्य की जगह साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

—x—x—

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. GDP can measure economic growth, but to measure economic development we need other indicators as well. Discuss.
जी.डी.पी. से आर्थिक संवृद्धि की माप की जा सकती है, लेकिन आर्थिक विकास को मापने के लिए हमें अन्य संकेतकों की भी आवश्यकता होती है। चर्चा कीजिए।

किसी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमाओं के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को GDP कहा जाता है।
इसको प्रतिव्यक्ति आय के रूप में आर्थिक संवृद्धि मापने का एक कारक माना गया है क्योंकि यह लोगों की आय में वृद्धि की माप करता है।

GDP : आर्थिक संवृद्धि मापक के रूप में

आर्थिक संवृद्धि से आशय अर्थव्यवस्था में लोगों की आय में हुई वृद्धि से होता है।

① प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्र की संवृद्धि प्रदर्शित करती है।

② इससे लोगों की क्रय शक्ति में सुधार होता है तथा उनका उपभोग स्तर बढ़ता है।

③ GDP संवृद्धि अधिक निवेश आकर्षित करती है जिससे लोगों की प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यद्यपि GDP के आधार पर भारत, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अर्थात् भारत को विकसित राष्ट्रों में शामिल होना चाहिए था किन्तु ~~GDP व सिर्फ आर्थिक~~ विशाल गरीब आबादी, अशिक्षा आदि के आधार पर भारत को विकसित नहीं कहा जा सकता है। अतः आर्थिक विकास मापने अन्य संकेतकों की आवश्यकता है।

आर्थिक विकास मापने अन्य संकेतकों की आवश्यकता

(A) GDP की कमियाँ: (1) GDP अर्थव्यवस्था में उपस्थित आर्थिक विषमता का मापन नहीं करती अर्थात् शीर्ष लोगों के पास आय से बढ़ोत्तरी से भी GDP बढ़ सकती है जबकि दूसरी ओर निम्न स्तर पर आय में कमी हो।

(2). GDP अर्थव्यवस्था में गैर-मौद्रीकृत आय (महिला द्वारा परिवार में पालन-पोषण का मूल्य) का मापन नहीं होता।

(3) GDP नकारात्मक बाह्यताओं से भी वृद्धि कर सकती है जिनका आर्थिक ~~वि~~ विकास पर नकारात्मक प्रभाव होता है जैसे, सिगरेट उत्पादन में वृद्धि से GDP में वृद्धि किन्तु विकास पर हानिकारक प्रभाव।

(4) इसके अतिरिक्त विकासशील राष्ट्रों में असंगठित क्षेत्रों की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विशाल उपस्थिति होती है जिसका मापन GDP में नहीं किया जाता।

(B) विकास बहुआयामी धारणा है: संवृद्धि की अपेक्षा विकास बहुआयामी है जिसका केवल एक आधार आय वृद्धि से मापन संभव नहीं है इसके ~~लिए~~ मापन के लिए बहुआयामी संकेतकों की आवश्यकता होती है जैसे

- Human Development Index (स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा)
- Human Capital Index
- multiDimensional Poverty Index
- Gender Gap Report

ये सभी Index विभिन्न बहुआयामी संकेतकों के माध्यम से किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास की स्थिति का वर्णन करते हैं भारत में इन्हीं की तर्ज पर आर्थिक विकास के मापन हेतु नीति आयोग द्वारा – भारत SDG Index तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में MDP Index का विकास किया गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. What do you understand by the term 'National Income'? Explain the various factors affecting national income of a country.
'राष्ट्रीय आय' पद से आप क्या समझते हैं? किसी देश की राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए।

किसी राष्ट्र के निवासियों द्वारा अर्जित ~~समय~~ समस्त आय (वित्तीय वर्ष में) को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसको सामान्यतः Net ~~Domestic~~ National Product at Factor Cost पर मापा जाता है।

राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियाँ हैं।

- व्यय विधि
- उत्पादन विधि
- आय विधि

राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक

(1) नागरिकों के मध्य बचत : बचत की अधिक मात्रा अधिक निवेश का सृजन करती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

(2) आयात - निर्यात की मात्रा : अधिक आयात व न्यून निर्यात से आय को बड़ा भाग विदेश में स्थानांतरित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होता है जिससे राष्ट्रीय आय में कमी आती है।

(3) सरकार की भूमिका

a. लिये गये विदेशी ऋण पर ब्याज अदायगी राष्ट्र के आय को बाहर भेज देती है।

b. ~~सरकार~~ सरकार द्वारा निवेश में की गई कमी भी राष्ट्रीय आय को कम करती है।

(4) अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर

a. अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप अधिक आय प्राप्त होती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

(5) मानव पूँजी की स्थिति

a. कौशल व सशक्त मानव पूँजी विदेशी आय का अर्जन, गुणवत्ता व दक्षता के अधिक उत्पादकता में संलग्न होती है जिससे राष्ट्रीय आय ~~प्रभावित~~ बढ़ती है।

(6) भ्रष्टाचार व समानांतर अर्थव्यवस्था की उपस्थिति

आय के बड़े हिस्से को अर्थव्यवस्था से बाहर कर देते हैं जिससे राष्ट्रीय आय में कमी आती है।

राष्ट्रीय आय की किसी भी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के मापन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा उसी के आधार नागरिकों की आय क्षमता व जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी होती है अतः भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के प्रयास किये जाना चाहिए।

———— × ———— × ————

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Mention the various sources of external borrowings available to the government. What is the significance of external borrowings in India's debt profile?

सरकार के समक्ष उपलब्ध बाह्य उधारियों के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। भारत के ऋण पोर्टफोलियो में बाह्य उधारियों का क्या महत्व है?

बाह्य उधारियों से आशय विदेशी संस्थागत स्रोतों से प्राप्त ऋणों से होता है। भारत में कुल उधारियों में बाह्य उधारियों का हिस्सा स्थिर है तथा सरकार से अधिक निजी क्षेत्र द्वारा निधारित किया गया है।

सरकार के समक्ष बाह्य उधारियों के प्रमुख स्रोत

① अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार: जैसे- वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि द्वारा भारत को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है।

② बाह्य संस्थागत निवेशकों से ऋण: भारत बाण्ड, ट्रेजरी बिल आदि माध्यम से ऋण प्राप्त करती है।

③ विदेशों में मसाला बाण्ड जारी करना: इसके माध्यम से भारतीय रुपये में विदेशों से ऋण प्राप्त किया जाता है।

④ NRI जमाएं :- इन्हें भी ~~भारतीय~~ विदेशी ऋण का प्रमुख स्रोत माना जाता है।

ऋण पोर्टफोलियो में बाह्य उधारियों का महत्व

① भारत में Crowding out effect से रक्षा

यदि सरकार घरेलू बाजार से ऋण प्राप्त करे तो भारत में दरों में वृद्धि के इस प्रभाव का खतरा।

② सस्ती दर

भारत में ब्याज दरें विदेशी दरों से अधिक।

③ विकासात्मक व्यय हेतु आसान व दीर्घकालिक ऋण

विकास संस्थान जैसे World Bank भारत में गरीबी निवारण आदि हेतु सस्ती दरों पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं जिससे भारत पर एकाएक बोझ नहीं बढ़ता।

④ अनुशासन राजकोषीय अनुशासन

चूँकि बाह्य ऋणों को सही समय पर भुगतान न होने से सरकार संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में गिरावट होती है अतः सरकार इसके प्रयोग में जवाबदारी रखती है।

⑤ विदेशी मुद्रा का अर्जन

बाह्य ऋण से भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति जिसका सरकार वित्तीय स्थिरता बनाये रखने में प्रयोग करती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यद्यपि बाह्य उधारियों के लाभ हैं किन्तु इनका खतरा भी रहता है जैसे मुद्रा के अवमूल्यन से अधिक राशि का भुगतान, IMF आदि संस्थाओं द्वारा सशर्त ऋण, अधिक उधारी राष्ट्र में अस्थिरता लाती है तथा मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से मुद्रा स्फीति दबाव भी उत्पन्न हो सकता है

अतः सरकार को बाह्य उधारियों को सीमित रखना चाहिए तथा उन्हें अधिक-अधिक रु मूल्यवर्ग में प्राप्त करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. What is performance budgeting? Discuss its objectives, components and functioning in India.
निष्पादन बजट क्या है? भारत में इसके उद्देश्यों, घटकों और कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए।

निष्पादन बजट, पारम्परिक बजट से आगे बढ़ने का प्रतीक है। इसमें निश्चित मौद्रिक मूल्य लक्ष्यों (कितना किया जा रहा है) के स्थान पर मापनीय परिणामों (किये गये का लाभ कितना) के आधार पर बजट तैयार किया जाता है।

निष्पादन बजट के उद्देश्य

① नीतियों में सकारात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से परिणामों को सुधारना।

② चूंकि बजट का निर्धारण परिणामों के आधार पर होता है अतः जनता के प्रति जवाबदेही का निर्माण होता है।

③ योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण उन्हें निश्चित दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है।

④ लघु व दीर्घकालिक लक्ष्यों में संबंध को स्पष्टता प्रदान की जाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निष्पादन बजट के घटक

(1) नीतियों के परिणामों का आंकलन करने हेतु Data set.

(2) मध्यकालीन व दीर्घकालीन लक्ष्यों का आँकलन।

(3) मध्यावधि रिपोर्ट जो लक्ष्य की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

(4)

भारत में कार्य प्रणाली

(1) भारत में अधिकतर योजनाओं को राज्यों के माध्यम से लागू किया जाता है अतः इसमें राज्यों की अहम भूमिका।

(2) योजनाओं का मापन निश्चित Data sets के अन्तर्गत किया जाता है।

(3) यह योजनाओं के मध्य में अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता पूरी करता है।

(4) ∵ सरकार पर जनता की नजर होती है अतः लेखविभाग में दक्षता व अनुशासन का ध्यान रखा जाता है।

कार्य प्रणाली से जुड़े मुद्दे

(1) ~~सरकार द्वारा~~ राज्यों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) आपक Data set सभी योजनाओं पर उपलब्ध नहीं तथा जहाँ उपलब्ध हैं वहाँ मापक में बाधा उत्पन्न करते हैं।

(3) इस संबंध में मंत्रालयों में परिणामों व उनके निहतार्थों की संबद्धता के निर्धारण की समस्त कम है।

(4) यह अधिक खर्चीली व समय लेने वाली प्रक्रिया है।

यद्यपि यह मुद्दों से युक्त है किन्तु ~~सार्व~~ सामाजिक अंकेक्षण आदि माध्यमों को शामिल कर तथा वक्ता; व प्रभावित द्वारा इसे भारत में सफलता पूर्वक लागू किया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Give an account of the value added, income and expenditure methods of estimating the national income of a country.

किसी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करने की मूल्यवर्धित, आय और व्यय विधियों का विवरण दीजिए।

किसी देश के समस्त निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है।

राष्ट्रीय आय = $(NNP)_{FC}$

राष्ट्रीय आय आंकलन की मुख्यत: 3 विधियाँ हैं

- मूल्यवर्धित
- आय
- व्यय

मूल्यवर्धित विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन

किसी फर्म द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु/सेवा के कुल मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाने के पश्चात कुल मूल्यवर्धन प्राप्त होता है जिसे सामान्यत: GVA कहते हैं।

तथा सभी फर्मों का कुल GVA राष्ट्रीय आय कहलाती है

अत: राष्ट्रीय आय = Σ GVA

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आय विधि से राष्ट्रीय आय

अर्थव्यवस्था के सभी भागों द्वारा, अर्जित
अंतिम रूप से

कारक और गैर कारक आयों का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है।

अतः

राष्ट्रीय आय = ब्याज + मजदूरी + किराया + लाभ

व्यय विधि से राष्ट्रीय आय

अर्थव्यवस्था में घरेलू, सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा किया गया कुल व्यय राष्ट्रीय आय है।

$$NI = C + G + I + (X - M)$$

C = घरेलू क्षेत्र द्वारा सम्पूर्ण व्यय

G = सरकार द्वारा कुल व्यय (निवेश छोड़कर)

I = निजी क्षेत्र व सरकार दोनों द्वारा कुल निवेश

X-M = ~~आयात~~ निर्यात - आयात का मान

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न क्षेत्र के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। जहाँ सेवा क्षेत्र की आय,

VISION IAS™
Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आय विधि द्वारा, निर्माण क्षेत्रक की व्यय विधि द्वारा तथा विनिर्माण व कृषि क्षेत्रक की आय की गणना हेतु मूल्यवर्धित विधि का उपयोग किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Enumerating the objectives of land reforms in post-independence India, highlight the measures taken in this regard.
स्वातंत्रोत्तर भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते हुए, इस संबंध में किए गए उपायों पर प्रकाश डालिए।

स्वतंत्रता के समय भारतीय शासन के समक्ष बहुत बड़ी समस्या भूमि सुधारों की थी जिसका वादा ~~हर~~ सम्पूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन में किया गया था।

भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य

① भूमि का पुनर्वितरण : स्वतंत्रता के समय भूमि की विशाल मात्रा, न्यून हाथों में ~~कि~~ केन्द्रित थी जिसे सुधारने की आवश्यकता थी।

② उत्पादन में वृद्धि : भूमि की उत्पादकता अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा कम थी।

③ काश्तकारों को भूमि अधिकार : जो प्रायः लम्बे समय से भूमि पर कृषक किन्तु स्वामित्व से वंचित थे।

④ ~~भूमि~~ वितरणमूलक न्याय की स्थापना : जिसका आदेश नीति-निदेशक तत्वों में दिया गया था।

(5) आर्थिक विकास हेतु व विकासात्मक कार्यों हेतु भूमि उपलब्धता में वृद्धि करना।

(6) भूमि स्वामित्वाधिकार स्पष्ट कर भूमि विवादों को न्यून करना।

(7) महिलाओं के भू:, परम्परागत वन वासियों को भूमि अधिकारों को मान्यता प्रदान करना।

भूमि सुधार के संबंध में किये गये उपाय

---

(1) जमींदारी प्रथा उन्मूलन हेतु जमींदारी उन्मूलन कानून का अधिनियम।

(2) किस किरायेदारों के अधिकार रक्षा हेतु किरायेदारी अधिनियम का अधिनियम।

(3) भूमि की उच्चतम सीमा (हदबंदी) निर्धारित की गई तथा शेष भूमि का पुनर्वितरण किया गया।

(4) चकबंदी व सरकारी भूमि का प्रयोग कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि की गई।

(5) भूमि अधिग्रहण अधिनियम -2013 द्वारा

भूमि अधिग्रहण के संबंध में उच्च मुआवजे का निर्धारण।

(6) परम्परागत वनवासी (भूमि अधिकार) अधिनियम-2006 द्वारा वनवासियों को भूमि अधिकारों की व्यवस्था की गई।

(7) PESA अधिनियम 1996 द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग हेतु ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य।

(8) वर्तमान में भूमि स्वात्वाधिकारों का डिजीटलकरण हेतु राष्ट्रीय डिजीटलीकरण कार्यक्रम तथा स्वामित्व योजना संचालित की जा रही है।

यद्यपि इन कार्यक्रमों से सुधार हुआ है किन्तु महिलाओं को भूमि अधिकार मिलने, वनवासियों को वास्तविक अधिकार देने तथा भारत में भूमि के स्पष्ट मलिकाना हक की रूपरेखा निर्धारण हेतु भी प्रयास किये जाने चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Give an account of the composition and functions of the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India.
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना और प्रकार्यों का विवरण दीजिए।

भारत में उर्जित पटेल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर मौद्रिक नीति के संचालन हेतु मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था।

मौद्रिक नीति समिति की संरचना

~~(1) अध्यक्ष~~ · समिति 6 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI तथा सरकार दोनों के सदस्य शामिल होंगे।

(1) अध्यक्ष के रूप में RBI गवर्नर।

(2) RBI एक मौद्रिक नीति संबंधी डिप्टी गवर्नर।

(3) RBI का अन्य गवर्नर।

(4) सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य, जिनका चयन केन्द्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मौद्रिक नीति समिति के प्रकार्य

① ~~मुद्रास्फीति~~ लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण :- आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना।

② सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य 2-4±2% के भीतर मुद्रास्फीति का नियंत्रण।

③ इस हेतु समिति प्रत्येक 2-माह पर बैठक करेगी तथा Policy Rate जारी करेगी।

④ मुद्रास्फीति को लगातार 2 ~~तिमाहि~~ तिमाहीयों तक लक्ष्य के भीतर न रख पाने पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

⑤ राजकोषीय नीति के साथ मिलकर वित्तीय प्रणाली को स्थिरता प्रदान करना।

⑥ मंदी के समय इसके द्वारा ~~लचील~~ प्रसारणशील नीति अपनाई जाती है जिसमें नीति दरों को कम किया जाता है तथा अधिक मुद्रास्फीति की दशा में संकुचित नीति का पालन किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में मौद्रिक समिति

मौद्रिक नीति में सरकारी हस्तक्षेप को कम करती है, राजकोषीय नीति के साथ संलग्नता रखती है तथा अपने मीटिंग मिनिट्स जारी कर पारदर्शिता बनाए रखती है इसलिए अभी तक अपना कार्य सफलता पूर्वक किया है उसे आगे भी जारी रखा जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Explaining the reasons for the poor monetary policy transmission in India, highlight the measures that can be taken to address the issue.

भारत में खराब मौद्रिक नीति संचरण के कारणों को स्पष्ट करते हुए, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर प्रकाश डालिए।

भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है जिसमें RBI तथा सरकार दोनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

भारत में खराब मौद्रिक नीति संचरण के कारण

(1) बैंकों द्वारा अनुपालन में समय : बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति संबंधी प्रभावों को अपनाने में देरी की जाती है तथा ~~x~~ उनकी ऋणों दरों का निर्धारण दरों MCLR आदि के कारण देरी होती है।

(2) राजकोषीय नीति से समन्वय का अभाव : भारत में दोनों के मध्य समन्वय का अभाव देखा जाता है।

(3) ~~अ~~ विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ~~समस्याएं अधिक~~ संरचनात्मक समस्याएं अधिक हैं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिसके कारण मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है।

(3)

समाधान के लिए किये जा सकने वाले उपाय

(1) बैंकों को रेपो रेट या अन्य बैंचमार्क दरों से Landing Rate संबंधित करना, जैसा RBI द्वारा निर्देश किया गया है।

(2) भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना।

(3) राजकोषीय नीति में से प्रभावी समन्वय रखना। सरकार द्वारा

(4) सरकार द्वारा लोकलुभावन नीतियों से बचना जिससे मौद्रिक नीति पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न न हो।

(5) मौद्रिक नीति समिति को अनुपालन के मामले में अधिक अधिकार प्रदान करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारती COVID-19 के पश्चात्
भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाये रखने हेतु मौद्रिक नीति अत्यधिक महत्व है अतः उसका संचालन सुचारु रूप से किया जाना आवश्यक है।

———x———x———

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Explain the objectives and significance of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003. What shortcomings have been observed in its implementation over the years?

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के उद्देश्यों और महत्व को स्पष्ट कीजिए। विगत कुछ वर्षों में इसके कार्यान्वयन में क्या दोष देखे गए हैं?

सार्वजनिक वित्त पर पारदर्शिता तथा राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2003 पारित किया गया था।

FRBM अधिनियम, 2003 के उद्देश्य

① लोकवित्त में पारदर्शिता : सरकार 3 प्रमुख रिपोर्टों का ~~प्रकाश~~ प्रकाशन करना अनिवार्य:

① Fiscal ~~stat~~ ~~start~~ Policy staratagy statement
② Medium term Fiscal Policy statement
③ macro economic Policy statement

② राजकोषीय उत्तरदायित्व : सरकार के सभी प्रकार के घाटों (राजकोषीय, बजट, राजस्व आदि) का को निश्चित ~~सत्~~ समय सीमा के भीतर अधिनियम

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर लाना।

(3) राजकोषीय समेकन:- सरकार पर अपनी आय-व्यय संबंधी नीतियों में सुधार का दायित्व।

अधि-का महत्व

(1) भारत में राजकोषीय घाटा निश्चित सीमा के भीतर बना हुआ है।
यहाँ तक कि COVID के समय भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत का राजकोषीय प्रदर्शन अच्छा रहा है।

(2) सरकार द्वारा राजस्व घाटे को लगातार कम करने संबंधी प्रयास किये जा रहे हैं।
जैसे; ~~सैन्य बलों~~ - पेंशन की समाप्ति।

(3) सरकारी व्यय को राजस्व के स्थान पर पूंजीगत क्षेत्र में अधिक ~~किया~~ स्थानांतरित किया गया है।

(4) सरकार के ~~अ~~ ऊपर संसदीय जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है जिससे अनावश्यक व्यय में कमी आई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यद्यपि कुछ कमजोरियाँ/खामियाँ, अधिनियम के लक्ष्यों की समय सीमा बार-बार बढ़ाना तथा लगातार लक्ष्यों की अप्राप्ति जैसे मुद्दे विद्यमान रहे हैं किन्तु अधिनियम ने राजकोषीय समेकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

NK सिंह समिति की सिफारिशों को लागू कर इसको और अधिक मजबूती प्रदान की जानी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. State the factors behind the menace of Non-Performing Assets (NPA) in India. What steps can be taken to address it?

भारत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के संकट के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

~~ऐसी परिसंपत्तियाँ~~ उधार परिसंपत्तियाँ जिन पर लगातार 90 दिनों तक न तो ब्याज की किश्त और न ही मूलधन की वापसी हो उन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्णित किया जाता है।

NPA के कारण समस्याएँ

- वित्तीय क्षेत्र पर दबाव
- पूँजी का अभाव
- निवेश में कमी
- पूँजी निर्माण में कमी
- ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी

NPA संकट के लिए उत्तरदायी कारक

(1) खराब प्रबंधन :- ऋण प्राप्तकर्ता के पर्याप्त आँकलन के बिना ऋण प्रदान करना, ऋणों का खराब प्रबंधन।

(2) Twin Balance sheet Problem : जिसके कारण बैंकों पर दोहरा बोझ ~~पड़~~ पड़ रहा है।

③ सरकार की लोकलुभावन नीतियाँ: कृषि ऋण माफी जैसी योजनाओं ने बैंकों पर दबाव डाला है।

④ सरकारी बैंकों का खराब प्रदर्शन: लगभग 65% NPA सरकारी बैंकों स्पष्ट रूप से अनियमितता की आशंका पैदा करते हैं।

⑤ IF&LS की असफलता: ने बैंकिंग sector पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया है।

उठाये जा सकने वाले कदम

① ~~RBI की~~ बेसल मानदण्डों का सख्ती से पालन लागू करना।

② RBI को 'SR' रणनीति को लागू करना।

③ सार्वजनिक बैंकों का विलय तथा निजीकरण उन्हें दक्षता व प्र: नये प्रबंधन से जोड़ेगा।

④ बैंकों का पुनर्पूंजीकरण।

⑤ मिशन इन्द्रधनुष जैसी योजनाओं का संचालन।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) EASE 3.0 को प्रारंभ करना।

(7) कार्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार जिससे क्षेत्र में नयी पूँजी का आगमन होगा।

(8) सरकार द्वारा लोकलुभावन नीतियों पर नियंत्रण।

(9) साख ब्यूरो की केन्द्रीय रिपाजरी का निर्माण।

NPA की समस्या धीरे - धीरे नियंत्रण में आने लगी है किन्तु सरकार को व RBI को नियंत्रण बनाये रखना चाहिए ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे व निवेश हेतु धन सदा उपलब्ध रहे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Identifying the rationale behind gender budgeting, discuss the challenges faced in its effective implementation in India.

जेंडर बजटिंग (महिलोन्मुखी बजट) के पीछे तर्क की पहचान करते हुए, भारत में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के समक्ष आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Explain the demand-pull and cost-push factors of inflation. Also highlight some monetary and fiscal measures that can be taken to control inflation.
मुद्रास्फीति के मांग-प्रेरित और लागत-प्रेरित कारकों की व्याख्या कीजिए। साथ ही, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए जा सकने वाले कुछ मौद्रिक और राजकोषीय उपायों पर भी प्रकाश डालिए।

औसत कीमत स्तरों में लगातार वृद्धि या मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली कमी को मुद्रास्फीति कहा जाता है।

मुद्रास्फीति के मांग-प्रेरित कारक

① भारत की जनसंख्या - अधिक जनसंख्या ~~अधिक मांग~~
↓
मांग > उत्पादन ⇒ मुद्रास्फीति

② घाटे का मौद्रीकरण :- अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि
↓
मांग ↑ → मुद्रास्फीति

③ ~~उच्च~~ आय स्तर: भारत में कुछ वस्तुओं के उपभोग में आय के साथ वृद्धि होती है (दूध, अण्डा, दाल) जिससे इनकी मांग में वृद्धि हुआ

④ प्रयोज्य आय में वृद्धि :- भारत में प्रयोज्य आय में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

⑤ विदेशी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि :- मुद्रा आपूर्ति ↑ → मांग ↑

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कारक

① मजदूरी में वृद्धि : उत्पादकता में वृद्धि किये बिना मजदूरी में वृद्धि जिससे लागत वृद्धि व कीमतों में वृद्धि।

② अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि → लागत वृद्धि → मूल्य में वृद्धि

③ न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि → से व्यापारियों की लागत में वृद्धि जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि।

④ अवसंरचनात्मक बाधाएँ (logistics लागत में वृद्धि) तथा मौसमी कारक (खराब मौसम से उत्पादन में कमी) आदि भी लागत जन्य कारक।

→ इसके अतिरिक्त भारत में पेट्रोलियम की आयात निर्भरता से यदि पेट्रोल - डीजल में बढ़ोतरी तो सामान्यतः सभी उत्पादों के कीमत स्तर में बढ़ोतरी होती है।

नियंत्रण हेतु राजकोषीय व मौद्रिक उपाय

(A) मौद्रिक उपाय

① संकुचन मौद्रिक नीति का संचालन जिससे मुद्रा ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो तथा ऋण लेने में कम रुचि के कारण मुद्रा आपूर्ति कम हो।

② Open market Operation :- RBI, सरकारी प्रतिभूतियों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को बाजार में विक्रय कर अतिरिक्त मुद्रा को सोख ले।

(3) CRR तथा SLR दरों में बढ़ोत्तरी जिससे साख ऋण हेतु कम धन उपलब्धता।

(B) राजकोषीय नीति

(1) ~~प्र.~~ प्रत्यक्ष करों में बढ़ोत्तरी तथा अप्रत्यक्ष करों में कमी।

(2) लोकलुभावन नीतियों पर नियंत्रण।

(3) ~~सब्सिडी में कमी।~~ उद्योगों को सब्सिडी में वृद्धि।

(4) ~~[illegible]~~ व्यय में कमी।

एक निश्चित स्तर पर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की प्रगति हेतु वांछित होती है अतः भारत में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत उस पर नियंत्रण रखा जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. What do you understand by cyclicality of the fiscal policy? In this context, also explain the meaning and significance of pro-cyclical and counter-cyclical fiscal policy.

राजकोषीय नीति की चक्रीयता से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, अनु-चक्रीय और प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति का अर्थ और महत्व भी स्पष्ट कीजिए।

अर्थव्यवस्था के मंदी तथा Boom चक्रों में राजकोषीय नीति का संचालन राजकोषीय नीति चक्रियता कहलाता है। तथा मंदी के चक्रों सरकार उदार राजकोषीय नीति अपनाती है तथा Boom चक्र में नियंत्रित रूप से व्यय करती है।

अनुचक्रीय राजकोषीय नीति

अर्थ :- अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए सरकार व्यय में वृद्धि करती है, करों में कटौती करती है तथा सब्सिडी बढ़ाती है। ~~जिससे अ~~

महत्व

1. अर्थव्यवस्था में माँग सृजित करना।
2. अर्थव्यवस्था में उत्पादन को पुनः प्रेरित करना।
3. रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाना।
4. अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना।
5. सकल पूंजी निर्माण दर में वृद्धि करना जिससे

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अर्थव्यवस्था पुनः गति प्राप्त कर लेे।

प्रति – चक्रीय राजकोषीय नीति

अर्थ → अर्थव्यवस्था के अच्छे दौर में सरकार अर्थव्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है तथा करों को बढ़ाती है। जिससे व तरलता को कम करती है।

महत्व

(1) वृद्धि से प्राप्त उच्च कर राजस्व का उपयोग आय पुनर्वितरण में किया जाता है।

(2) अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ती क्षमता में सरकार व्यय में कमी कर सकती है व अर्थव्यवस्था को स्वयं आगे आने का मौका देती है।

(3) नियामकीय सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जाती है।

(4) ~~आय वृद्धि~~ अर्थव्यवस्था के लाभों को समाज के सभी स्तरों तक पहुंचाया जाता है।

(5) RBI अपने विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि करती है।

राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार तथा पुनर्वितरण न्याय प्रदान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रदान करने में सरकार की सहायता करती है।
अत: विभिन्न भागों में सरकार को इसका सुचारु संचालन करना चाहिए।